भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1998

बुधवार, 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे

1998. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारों की स्थापना में तेजी लाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान बजट में कितनी धनराशि आबंटित की गई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी निधि जारी की जा रही है; और

(ग) क्या और अधिक देरी से बचने के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): सरकार चरण-1 के रूप में विजाग-चेन्नई औद्योगिक कोरीडोर (वीसीआईसी) सहित चेन्नई-बेंगलूरू औद्योगिक कोरीडोर (सीबीआईसी) और पूर्वी तट आर्थिक कोरीडोर (ईसीईसी) को विकसित कर रही है जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। सीबीआईसी के भाग के रूप में, आंध्र प्रदेश राज्य में विकास के लिए कृष्णापटनम नोड की पहचान की गई है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किए गए हैं और ''एनआईसीडीआईटी कृष्णापटनम इण्डस्ट्रीयल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड'' नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल की गई है। कृष्णापटनम नोड के कार्यशील क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्यकलापों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

वीसीआईसी के लिए, एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने परियोजना का कंसेप्ट डेवलपमेंट प्लान (सीडीपी) तैयार कर लिया है तथा चार नोडों अर्थात (i) विशाखापट्टनम (ii) मछलीपटनम (iii)

डोनाकोंडा और (iv) चित्तूर को विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। चिह्नित किए गए चार नोडों में से, दो नोड अर्थात विशाखापटनम और चित्तूर को प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकता वाले नोडों के लिए एडीबी द्वारा शुरूआती मास्टर प्लानिंग पूरी कर ली गई है।

(ख) और (ग): संपूर्ण देश में सभी औद्योगिक कारीडोर परियोजनाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कोरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट में 850.00 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीबीआईसी में कृष्णापटनम नोड के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) परियोजना में शुरूआती इक्विटी योगदान के लिए एनआईसीडीआईटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रूपये की राशि आबंटित और जारी की गई थी। चूंकि ये परियोजनाएं अभी विकास के चरण में है इसलिए इस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

****